


अपील संख्या 21/2019
अनवान मंगतुराम बनाम शेराराम वगैरह


.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
16-12-2019	<p>पत्रावली प्रार्थना पत्र के आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 पर बहस के दौरान कंहा कि अपीलान्ट मंगतुराम की मृत्यु दिनांक 24.03.2005 को हो चुकी है तथा उसके तीन पुत्र रतनलाल, उमेदसिह, बाबूलाल, तथा एक पुत्री उर्मिला है। अपीलान्ट मंगतुराम मृतक की जगह चारो वारिसान का नाम बतौर अपीलान्ट दर्ज किया जावे।</p> <p>रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 पर बहस के दौरान कंहा कि अपीलान्ट अर्सा पूर्व फौत हो चुका है। मुतक अपीलान्ट के अभिभाषक ने दिनांक 07.10.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट का देहान्त दिनांक 24.03.2005 को होना बतलाया। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की मृत्यु के 14 वर्ष बाद पेश किया गया है। उक्त अपील सन् 2001 से विचाराधीन चल रही है। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ दफा- 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश ही नहीं किया। मियाद प्रकरण 90 दिन होती है। दफा -5 के प्रार्थना के अभाव मे उक्त प्रार्थना पत्र अधूरा है इनको मियाद नहीं मिल सकती। मेन्डेटरी प्रावधान की अवहेलना की है। उक्त अपील दिनांक 24.07.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गई थी फिर भी मृत व्यक्ति के आधार पर गलत तथ्य पेश कर रेस्टोर करवाई गई है। अपील अबेट हो चुकी है। इसी स्तर पर अपील खारिज की जावे।</p> <p>रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक श्री विजय कुमार पारीक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2001 पृष्ठ 118, RRD 2015 पृष्ठ 119 H.C, RRD 2002 पृष्ठ 711, RRD 1995 पृष्ठ 82, RRD 1995 पृष्ठ 456, RCM PART -II का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।</p> <p>अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस का प्रतिउत्तर देते हुवे कंहा कि लेण्ड रिकॉर्ड में कभी अलग से प्रार्थना पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड अभितक नहीं आया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक मंगतुराम के जायज वारिसानो को बतौर अपीलान्ट दर्ज किया जावे।</p> <p>अपीलान्ट के अभिभाषक श्री धन्नेसिह राठौड़ ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1992 पृष्ठ 100, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।</p> <p style="text-align: center;">लगातार.....</p> <p style="text-align: center;">उपस्थित आयुक्त बीकानेर</p>	

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस, सम्पूर्ण मामले, उपलब्ध दस्तावेजात, पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अध्ययन/मनन किया।

न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है :-

इस मामले में मुख्य विवाद अपीलान्त मंगतुराम के फौत होने के संबंध में है। अपीलान्त मंगतुराम का देहान्त दिनांक 24.03.2005 को हुआ लेकिन अपीलान्त के अभिभाषक इस न्यायालय में दिनांक दिनांक 07.10.2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर सूचना दी। उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अभिभाषक अपीलान्त एव स्वयं अपीलान्त के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24.07.2017 को पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई, उसके बाद दिनांक 03.08.2017 को अभिभाषक अपीलान्त ने मंगतुराम अपीलान्त जरिये एडवोकेट की और से प्रार्थना पत्र पेश कर अपील को रेस्टोर करने का निवेदन किया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में दिये कारणों पर विश्वास करते हुवे दिनांक 14.08.2019 को अपील रेस्टोर की गई। अपील के रेस्टोर होने के बाद अभिभाषक अपीलान्त न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर कथन कर रहे कि अपीलान्त मंगतुराम की मृत्यु 24.03.2005 को हो गई। इतने समय तक अपीलान्त के अभिभाषक ने न्यायालय में मृत्यु की सूचना नहीं दी बल्की अपील को रेस्टोर भी करवा लिया। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 में भी कथन नहीं किया कि अपीलान्त की मृत्यु की सूचना इतने समय बाद क्यों पेश की। इतने समय पश्चात प्रार्थना पत्र में पूरा विवरण के साथ बताना चाहिये कि इनको मृत्यु की सूचना कब प्राप्त हुई। ना ही अभिभाषक अपीलान्त ने इतने समय बाद इनको मियाद में लेने का कथन किया। किसी भी मामले में मियाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और व पक्षकारों के बीच में अधिकारों का सृजन एव विलोपन करने की क्षमता रखने वाला बिन्दु है। यह तो अभिभाषक अपीलान्त का कर्तव्य था कि वह अपनी अपील के सम्बन्ध में समय समय पर अपीलान्त से जानकारी लेता। इस प्रकार प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2019 विलम्ब से पेश करना साबित होता है। विलम्ब को कोई युक्ति युक्त कारण नहीं बताये बिना देरी की 14 वर्ष की अवधि को इतने समय बाद माफ नहीं किया जा सकता। अपील के शेष बिन्दुओं के गुणा व अवगुण पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक आयुक्त
बीकानेर

